गुलामी का नया दौर

-मनोज कुमार झा

कांग्रेस की हालत ख़सताहाल है। देश के अर्थव्यवस्था रसातल में चली जा रही है, पर सोनिया-मनमोहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 'युवराज' राहुल ख़ामोश हैं। ऐसा लगता है, सोनिया उन्हें ज़बरदस्ती राजनीति के रंगमंच पर घसीटकर लाना चाहती हैं। पर राहुल देश की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने के प्रति अनिच्छुक नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 'मौनव्रती' हैं और वाचाल दिग्विजय राहुल टीम की विश्वस्त नेत्री नटराजन को। 'सौ फ़ीसद टंच माल' कह कर मीडिया में भरपूर सुर्ख़ियां बटोर चुके हैं।

दरअसल, सौ फ़ीसद लुटेरों के गिरोह में बदल चुके हैं ये हुक्मरान। जनता का इनपर ज़रा भी भरोसा नहीं रहा। जनता को कोई विकल्प भी दिखाई नहीं पड़ रहा। यूपी हो या बिहार, बंगाल हो या महाराष्ट्र, हर जगह सत्ता पर लुटेरे काबिज़ हैं।

ग़रीबी सातवें आसमान पर चली गई, रुपया पाताल में समाता चला जा रहा है। दुधमुंहें बच्चे को लेकर औरतें जिस्म का सौदा करने बाज़ारों में भटक रही हैं। ऐसी रिपोर्टें मीडिया में आ रही हैं।

अपने आपको इस दुनिया का सरताज समझने वाला अमेरिका भी भीषण मंदी की मार से कराह रहा है। नैतिक मूल्य शून्य से नीचे लुढ़क गए। सामाजिक व्यवस्था उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। माओ का चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनकर उभर रहा है। ऊंचे तबके के मर्दों और औरतों को फ़ुर्सत नहीं कि वे एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुक भी बना सकें। अकेलेपन की गहरी अंधेरी खाई में सभी डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे में, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चीन बाज़ार की जरूरतों को समझते हुए विश्व में सेक्स ट्वॉयज का सबसे बड़ा निर्माता और व्यापारी बनकर उभरा है। सैन्य ताकत में उसका मुकाबला अमेरिका और रूस को छोड़ कर शायद ही कोई दूसरा मुल्क कर सके।

वह भारत को लगातार धमकाता रहता है और उसके चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की पीठ थपथपाता रहता है।

केंद्र की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर पूरे देश में अलगाववादी ताकतें सिर उठा रही हैं। केंद्र सरकार ने सीबीआई को अपना औजार बना रखा है और न्यायपालिका को भी खिलौने से ज़्यादा नहीं समझती।

इन हालत में, देश का क्या होगा, खुदा ही जानता है। जनता में शासकों के प्रति घृणा का भाव स्पष्ट नज़र आता है। पर वह बेचारी बनी हुई है। दो जून की रोटी और नमक का जुगाड़ बहुत मुश्किल भरा है। इसी के जुगाड़ में पौ फटते रात का अंधेरा सधन हो जाता है और इस बीच न जाने कितनी दुश्वारियां।

जनता तो महज वोट देने की मशीन में बदल चुकी है। तमाम मीडिया कंपनियां जो देशी और विदेशी कॉरपोरेट्स के हवाले हैं, अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर मुहिम चलाने में लगी हुई हैं।

बुद्धिजीवी 'प्रतिष्ठानों' के हवाले हैं। जो उनके बाहर हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। कुछ मोदी की जय-जयकार में लगे हुए हैं तो कुछ सोनिया के, जो बाकी बचे वो क्षत्रपों के दरबार में स्तुति-गायन में लगे है।

पूरा राजनीतिक तंत्र पूंजीपतियों और माफिया सरगनाओं के हवाले है। सारा माहौल अराजक-सा होता चला जा रहा है। ऐसे में आने वाले चुनावी वर्ष में क्या होगा, कह पाना मुश्किल है।

विकल्प की शक्तियां कहीं नज़र नहीं आ रहीं। विकल्पहीनता का ये दौर पता नहीं कब तक चलेगी? इतना तो तय है कि दोनों प्रमुख गठबंधनों में से किसी का सत्ता में आ पाना मुश्किल लग रहा है।

ऐसे में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ेगी और लुटेरी ताकतें नंगी होकर नाचेंगी।

लगता है, देश गुलामी के एक नये दौर की ओर बढ़ता चला जा रहा है।

'ग़रीब' मारुति कंपनी पर तरस खाया सुरजेवाला ने

देश की सबसे बड़ी कार बनाने, बेचने व अभी तक भारी मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी मारुति ने कहा है कि सरकार द्वारा मानेसर में उसको दी गयी ज़मीन पर यदि कोर्ट के आदेश के अनुसार उससे और ज़्यादा कीमत वसूल की गयी तो वह अपना कारखाना कहीं और ले जाने पर मजबूर होगी। इस पर हरियाणा के उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आश्वासन दिया कि सरकार कार कंपनी के बोझ को कम करने के लिये कदम उठायेगी। ध्यान रहे कि 'हूडा' से प्लाट लेकर मकान बनाने वाली इस प्रदेश की ग़रीब जनता ऐसे बोझ अनेकों बार उठा चुकी है लेकिन सरकार ने उनका 'बोझ' कम करने की कभी नहीं सोची।

गौरतलब है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानि 'हूडा' और एच एस आई आई डी सी आदि सरकारी विभाग ज़मीन मालिकों से ज़मीन अधिग्रहण करके उसको रिहायशी या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बेचते हैं। यदि ज़मीन मालिक कोर्ट से अपनी ज़मीन की ज़्यादा कीमत पा लेता है तो यह बढ़ी कीमत 'हूडा' से प्लाट खरीदने बालों से वसूल की जाती है। इसको 'एनहान्समेन्ट' कहा जाता है। अभी हिसार में हाल ही में सैक्टर 15 में पलाट लेने के 30 साल बाद 'एन्हान्समेन्ट' आ गयी है। गुड़गांव में करीब 15 साल बाद बढे रेट जनता से वसूले जा रहे हैं। लेकिन किसी तरह से बमुश्किल एक मकान बना पा लेने वाले इन लोगों पर रहम करने की इस सरकार ने कभी नहीं सोची।

ध्यान रहे कि मारुति सुजुकी एक प्राइवेट कंपनी है ओर भारी मुनाफ़ा कमा रही है। और यह वही कंपनी है जिसने अपने मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने की बजाय उनकी हड़ताल तोड़ने के लिये अपने इसी भारी मुनाफ़ा कमाने वाले मानेसर प्लाण्ट को कई महीने बन्द रखना ज़्यादा पसन्द

किया। रिहायशी इलाकों में अनेकों 'एनहान्समेन्ट' झेल चुकी हरियाणा की जनता का हक बनता है कि वह रणदीप सुरजेवाला का कालर पकड़कर पूछे कि हमारा बोझ कब कम करोगे? अरे भाई अगर ज़्यादा बोझ हो गया है तो ये कारखाना मज़दूरों को क्यों नहीं सौंप देते।

और बेचारे 'गरीब' अंबानी का बोझ मोईली ने कम किया

उधर हरियाणा में सुरजेवाला मारुति की ग़रीबी दूर करने में जुटे हैं तो इधर मोईली ने अम्बानी की गरीबी दूर करने की ठान ली है। अम्बानी को कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में डी-6 क्षेत्र में गैस निकालने का ठेका मिला था। बेचारे ग़रीब को कितनी तिकड़मों से यह ठेका मिला था उसमें हम नहीं जायेंगे। हम तो यह बता दें कि इनके ठेके में तकरीबन 2.2 डालर पर यूनिट पर सरकार को सन् 2014 तक गैस बेचने की शर्त थी। जब इन्होंने अपना घिसा पुराना कोट और पैंट दिखाया तो सरकार ने 2008 में इनकी ग़रीबी पर तरस खाते हुए इनसे तकरीबन 4.2 डालर प्रति यूनिट पर गैस खरीदना मान लिया।

यह अलग बात है कि इन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों के फटे पाजामें इस सरकार को कभी नहीं दिखे। (शायद चुनाव के वक्त प्रति वोट एक-एक पाजामा सिलवा दिया जाये) लेकिन फ़िर भी इनके कुओं से गैस उत्पादन बढ़ने के बजाय कम ही होता चला गया तो मंत्री महोदय जयपाल रेड्डी ने इनपर ठेके की शर्तों के अनुरूप 7000 करोड़ रुपया कर जुर्माना लगा दिया। ये मंत्री महोदय तो बेचारे 'ग़रीब' की घिसी पैंट को फ़ाड़ ही देते अगर इनको हटाकर सोनिया और मनमोहन जी ने मोईली को मंत्री न बनाया होता। उन्होंने आते ही अर्न्तराष्ट्रीय गैस मूल्यों का हवाला देकर 2014 से गैस के दाम 8.4 डालर प्रति यूनिट करने की घोषणा कर दी। वैसे दिल से तो वे इस दाम को आगे से नहीं बल्कि पिछले साल से ही लागू करना चाहते थे लेकिन उससे बी.पी. एल नर कंकाल रूपी वोटों के नाराज होने का खतरा था; कि आपने तो इन अम्बानियों को हमारे से भी ग़रीब का दर्जा दे दिया। सो मोईली ने इसी में संतोष किया। वैसे देखने वाली बात यह है कि तकनीकी कारणों से बंद कर दिये गये कुओं में 2014 अप्रैल से फ़िर से उत्पादन शुरू होता है या नहीं। इधर कुछ बदतमीज किस्म के लोगों ने ग़रीब नवाज मोईली से यह सवाल कर दिया कि वह 7000 करोड़ रुपया जुर्माने की फ़ाइल का क्या हुआ? बेचारे भोले मासूम मोईली क्या जवाब देते। बोले वह फ़ाईल तो आज तक मेरे पास पहुंची ही नहीं। हो सकता है निचले स्तर पर कोई बाबू भी ग़रीबों का मददगार हो और उसीने किसी तिकड़म से फ़ाइल को रोक रखा हो। अब मंत्री में तो इतनी ताकत होती नहीं कि अपने आप फ़ाईल मंगवाकर कार्रवाई कर दें और वह भी अम्बानी जैसे 'गरीब मजलूम' के ख़िलाफ़।

सुना है अब अम्बानी ने एयरपोर्ट मेट्रो से भी हाथ खींच लिये। ठीक ही किया। पहले ही रुपये के अवमूलमन के कारण बेचारों का कई लाख करोड़ रुपया का साम्राज्य एक लाख करोड़ रुपया पर आ गया है। फ़िर एयरपोर्ट मेट्रो जैसी घाटे की लाईन वह क्यों चलाये। सरकार चलाये उसे। और उनके पैसे सूद समेत वापस दिलवाने को सरकार में मोईली जैसे नंगो की कोई कमी नहीं। अब ये तो इस देश के मज़दूरों, किसानों, छोटे दुकानदोरों और नौकरीपेशा लोगों ने देखना है कि देश की पीठ पर लदे इन मोईली, सुरजेवाला, हुड्डा, सोनिया, मनमोहन रूपी कूड़े के बोझ को कैसे उतार कर फेंका जाये।

-अजातशत्रु

तुर्की-ब-तुर्की

शिवपाल यादव मंत्री एवं मुलायम का भाई

"हमें आइएएस अधिकारियों की जरुरत नहीं, केन्द्र इन्हें वापस ले ले, हम राज्य सेवा के अधिकारियों से काम चला लेंगे।" (आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति के निलम्बन के प्रसंग में शिवपाल ने उक्त बात कही।)

हमारा कहना है-

तुम्हें तो आई ए एस और आई पी एस की क्या राज्य सेवा के अधिकारियों की भी जरुरत नहीं; राजतंत्र चलाने के लिये हर गांव कसबे व ज़िले में इनके अपनें पालतू माफिया जो बैठे हैं।

सी बी आई चीफ़ रणजीत सिन्हा

"डायरेक्टर सी बी आई की कार्य-अवधि 2 वर्ष से बढा कर 3 वर्ष कर देनी चाहिये।" (सीबआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया शपथपत्र)

हमारा कहना है-

2 वर्ष कार्य-अवधि का नियम लागू होने के बाद हर सीबीआई डायरेक्टर 2 वर्ष तक अपने समय के सत्ताधारियों के इशारे पर तरह-तरह के गुल खिलाता आया है; क्योंकि उसे सेवा-निवृत्ति के बाद 70 वर्ष की उम्र तक किसी न किसी संवैधानिक पद पर बने रहने का लालच रहता है। और अगर राज्यपाल बन गये तो उम्र की बाधा भी आड़े नहीं आती। यदि कार्य-अवधि 3 वर्ष की कर दी जाये तो सिन्हा साहब आप जैसों को यही गुल 2 के बजाये 3 वर्ष तक खिलाने पड़ेंगे।

परखवाड़े की मुस्कराहट

एक व्यक्ति गैस की लम्बी कतार में खड़ा-खड़ा ऊब गया। हताश हो कर उसने कहा, "जा कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दो जूते मार कर आता हूं।"

घंटों के बाद वह हताश वापस आकर गैस की उसी कतार में लग गया। किसी ने उसे टोका "क्या जूते मार आये?" उस व्यक्ति ने नहीं में सिर हिलाया, "वहां तो इससे भी बड़ी लाइन लगी है।"

परखवाड़े की नफ़रत

अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

श्रीनिवासन अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड